

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 63/2018 राजस्व अपील

1. रामस्वरूप पुत्र श्री झूथाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोली उपतहसील बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा अपीलान्त
बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसील उपतहसील बहरावण्डा जिला दौसा रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध नायब तहसीलदार बहरावण्डा निर्णय दिनांक 04.01.2018 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रामस्वरूप मु.न. 04/2017 अधारा 91 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम

उपस्थिति : श्री राजेन्द्र कसाना, अधिवक्ता अपीलान्त उप0।
: श्री चन्द्रशेखर टापरिया, राजकीय अधिवक्ता उप0।

:— निर्णय :—

दिनांक: 20.08.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का मोरोली द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्त नें संवत् 2074 में ग्राम मोरोली में स्थित आराजी खसरा नं0.580, 739/583, 611, 613, कुल रकबा 2.34 है0 किस्म गै.मु. बांध, नदी, पहाड (सिवायचक) पर गोहू की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है तथा अतिक्रमी का भूमि पर कब्जा पश्चातवर्ती है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्त अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 04.01.2018 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 04.01.2018 से व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को कोई सुनवाई व सबूत का मौका नहीं दिया ना ही पटवारी हल्का ने अपीलान्त के समक्ष भूमि का मौका देखा ना मौका रिपोर्ट बनाई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की झूठी व बेबुनियाद रिपोर्ट



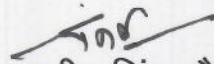
406
जिला कलक्टर
दौसा

को सही मानकर अपीलान्त को प्रश्नगत आराजी भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए दिनांक 04.01.2018 को निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी साबित नहीं है। अपीलान्त का प्रश्नगत राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं है तथा भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

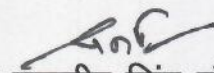
जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्त अतिक्रमी द्वारा संवत् 2074 में ग्राम मोरोली में स्थित आराजी खसरा नं0.580, 739/583, 611, 613, कुल रकबा 2.34 है0 किस्म गै.मु. बांध, नदी, पहाड (सिवायचक) पर गेहूं की काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 04.01.2018 के द्वारा अपीलान्त अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 30 दिन का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है, किन्तु अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की अपीलान्त का प्रश्नगत राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं है तथा भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अतः अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलान्त द्वारा ग्राम मोरोली तहसील सिकराय में स्थित आराजी खसरा नं0.580, 739/583, 611, 613, कुल रकबा 2.34 है0 किस्म गै.मु. बांध, नदी, पहाड (सिवायचक) पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने एवं भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत् शपथ पत्र उप तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष प्रस्तुत करने एवं उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अतिक्रमण हटा लिया जाना सत्यापित किया जाने पर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.01.2018 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।


(राजवीर सिंह चौधरी)
अति० जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 20.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।


(राजवीर सिंह चौधरी)
अति० जिला कलक्टर, दौसा

